पत्र सूचना कार्यालय (रक्षा विंग)
भारत सरकार
****
'हर काम देश के नाम'

नई दिल्लीः ज्येष्ठ 18, 1944
बुधवारः 08 जून 2022

डीआरडीओ की प्रौद्योगिकी विकास निधि योजना के अंतर्गत वित्त पोषण 10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये प्रति परियोजना किया गया

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय की प्रौद्योगिकी विकास निधि (टीडीएफ) योजना के अंतर्गत वित्त पोषण की राशि 10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये प्रति परियोजना करने को मंजूरी दे दी है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा निष्पादित टीडीएफ योजना, एमएसएमई और स्टार्ट-अप द्वारा घटकों, उत्पादों, प्रणालियों और प्रौद्योगिकियों के स्वदेशी विकास में सहायक है।

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय बजट 2022-23 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट का 25 प्रतिशत हिस्सा निजी उद्योग, स्टार्ट-अप और अकादमिक जगत के लिए निर्धारित किया गया था। बढ़ा हुआ वित्त पोषण बजट घोषणा के अनुरूप है और इससे 'रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता' की परिकल्पना को और बढ़ावा मिलेगा।

टीडीएफ योजना का उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भरता के पथ पर लाने के लिए रक्षा प्रौद्योगिकियों को नवोन्मेष और विकसित करने के लिए उद्योग को प्रोत्साहित करके रक्षा विनिर्माण क्षेत्र को एक बड़ा प्रोत्साहन प्रदान करना है। यह योजना कुल परियोजना लागत के 90 प्रतिशत तक की सुविधा प्रदान करती है और उद्योग जगत को किसी अन्य उद्योग/शैक्षणिक जगत के साथ सह-व्यवस्था में काम करने की अनुमति देती है। बढ़ाए गए वित्त पोषण के साथ, उद्योग और स्टार्टअप मौजूदा और भविष्य की हथियार प्रणालियों और प्लेटफार्मों के लिए अधिक जटिल प्रौद्योगिकियों को विकसित करने में सक्षम होंगे। अब तक, टीडीएफ योजना के अंतर्गत 56 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

एबीबी/डीके/डीएस/आरपी